



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 20 अगस्त, 1982

श्रावण 29, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वधायिका अनुभाग--1

संख्या 1548 / सत्रह-वि०-1-104-1980

लखनऊ, 20 अगस्त, 1982

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विविध (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 11 मई, 1982 ई० की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनाधर्मा अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1982)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901, जौनसार वावर जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956, उत्तर प्रदेश जौत चकवन्दी अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश अधिकतम जौत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 और उत्तर प्रदेश विधि (विहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

अध्याय एक

प्रारम्भिक

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा

संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ

(2) धारा 9, अक्टूबर 1980 को प्रवृत्त समझी जायेगी, धारा 19 पहली जुलाई, 1976 को प्रवृत्त समझी जायेगी, धारा 2 से 7 और 12 से 14 और 27 तब जून, 1981 को प्रवृत्त समझी जायेगी तथा धारा 8, 10, 11, 15 से 18 और 20 से 26 दस नवम्बर, 1980 को प्रवृत्त समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

### अध्याय दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
1 सन् 1951 की  
धारा 122-क का  
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे प्रागे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 122-ख में, उपधारा (1) से (4-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी; अर्थात्—

“(1) जहाँ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी गांव सभा या किसी स्थानिक आधिकारिकी में निहित किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी जाय या उसका दुविनियोजन किया जाय या जहाँ कोई गांव सभा या स्थानिक आधिकारिकी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा लेने या बनाये रखने का हकदार हो और ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न प्रकार से अध्यासन किया जाय, वहाँ, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक आधिकारिकी सम्बद्ध असिस्टेंट कलेक्टर को नियत रीति से सूचना देगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना से या अन्य प्रकार से असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गयी है या उसका दुविनियोजन किया गया है या उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कोई भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी व्यक्ति के अध्यासन में है, वहाँ वह सम्बद्ध व्यक्ति को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्षति, दुविनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिए ऐसी नोटिस में उल्लिखित प्रतिकर उससे क्यों न वसूल किया जाय या, यथास्थिति, क्यों न उसे ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाय।

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे व्यक्ति पर उस नोटिस के तारीख के दिनांक से तीन मास से अनधिक बढ़ाये गये समय के भीतर, जैसा असिस्टेंट कलेक्टर इस निमित्त बढ़ाने की अनुमति दे, कारण न बताये या यदि बताया गया कारण अपर्याप्त पाया जाय तो असिस्टेंट कलेक्टर यह निदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जाय और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो और यह निदेश दे सकता है कि क्षति, दुविनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन के लिये प्रतिकर की धनराशि ऐसे व्यक्ति से मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जाय।

(4) यदि असिस्टेंट कलेक्टर को यह राय हो कि कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में निर्दिष्ट क्षति या दुविनियोजन या दोषपूर्ण अध्यासन का दोषी नहीं है तो वह नोटिस को प्रभावान्मुक्त कर देगा।

(4-क) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर धारा 333 के खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित आधारों पर कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है।

(4-ख) इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत की जाय।

(4-ग) धारा 333 या धारा 333-क में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए—

(एक) इस धारा के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर का प्रत्येक आदेश उपधारा (4-क) और (4-घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा :

(दो) इस धारा के अधीन कलेक्टर का प्रत्येक आदेश उपधारा (4-घ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

(4-घ) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में असिस्टेंट कलेक्टर या कलेक्टर के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति में अपने द्वारा अध्यायित अधिकार को स्थापित करने के लिए सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में वाद दायर कर सकता है।

(4-ङ) असिस्टेंट कलेक्टर के किसी आदेश के विरुद्ध कोई ऐसा वाद जो उपधारा (4-घ) में निर्दिष्ट है, दायर नहीं किया जा सकता यदि उपधारा (4-क) के अधीन कलेक्टर को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर दिया गया हो।

**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद “कलेक्टर” का तात्पर्य यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है और उसके अन्तर्गत अपर कलेक्टर भी है।”

3—मूल अधिनियम की धारा 157-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

धारा 157-क  
का प्रतिस्थापन

“157-क (1) धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित जाति के किसी भूमिधर या असामी को कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा:

अनुसूचित जातियों के सद-  
स्यों, द्वारा भूमि के संक्रमण  
पर प्रतिबन्ध

प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर द्वारा ऐसा अनुमोदन नहीं किया जायेगा यदि संक्रमणकर्ता उस धारा के अधीन आवेदन-पत्र के दिनांक को उत्तर प्रदेश में 1.26 हेक्टेयर से कम भूमि धृत करता हो या उक्त दिनांक को संक्रमणकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे संक्रमण के पश्चात् 1.26 हेक्टेयर से कम हो जाने की सम्भावना हो।

(2) नियत रीति के उस निमित्त आवेदन पत्र दिये जाने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जैसी नियत की जाय।”

4—मूल अधिनियम की धारा 157-क के पश्चात् निम्नलिखित धारारें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्—

नई धारा 157-ख  
तथा 157-ग का  
बढ़ाया जाना

“157-ख—धारा 153 से 157 में निहित प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असामी को कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक या पट्टे द्वारा या अन्यथा संक्रमित करने का अधिकार न होगा।

अनुसूचित आदिम जाति के  
सदस्यों द्वारा भूमि के संक्र-  
मण पर प्रतिबन्ध

“157-ग—अनुसूचित जाति या कतिपय परिस्थितियों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के सदस्य द्वारा जोत को बन्धक रखना

अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिधर या असामी, धारा 157-क और 157-ख में निहित किसी बात के होते हुए भी धारा 152 की उपधारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में अपनी जोत या उसके भाग को कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है।

**स्पष्टीकरण**—इस अध्याय में, पद “अनुसूचित जातियों” और “अनुसूचित आदिम जातियों” का क्रमशः तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन उत्तर प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से है।”

5—मूल अधिनियम की धारा 163 निकाल दी जायगी।

धारा 163 का  
निकाला जाना  
धारा 166 और  
167 का प्रति-  
स्थापन

6—मूल अधिनियम की धारा 166 और 167 के स्थान पर निम्नलिखित धारारें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

“166—इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक संक्रमण शून्य होगा।

167 (1)—ऐसे प्रत्येक संक्रमण के सम्बन्ध में जो धारा 166 के कारण शून्य है, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

- (क) संक्रमण के दिनांक से संक्रमण की विषय वस्तु को सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;
- (ख) संक्रमण के दिनांक को उस भूमि में विद्यमान वृक्ष, फसल और कुशा को, उक्त दिनांक से, सभी भार से मुक्त राज्य सरकार में निहित समझा जायगा;
- (ग) संक्रमित संक्रमण के दिनांक को ऐसी भूमि में विद्यमान अन्य चल सम्पत्ति को या किसी अचल सम्पत्ति की सामग्री को ऐसे समय के भीतर जो नियत किया जाय, हटा सकता है।

(2) जहां कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो गई हो, वहां कलेक्टर को ऐसी भूमि या किसी अन्य सम्पत्ति पर कब्जा लेना और यह निदेश देना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी भूमि या सम्पत्ति पर अध्यासन करने वाले किसी व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय। ऐसा कब्जा लेने या ऐसे अप्राधिकृत अध्यासियों को बेदखल करने के प्रयोजनों के लिये कलेक्टर ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।”

7—मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (2-क) में, शब्द, अंक और अक्षर “धारा 157-क” के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर “धारा 157-क और 157-ख” रख दिये जायेंगे।

धारा 169 का  
संशोधन

धारा 197 का  
संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 197 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) को जायेगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा की जायेगी, अर्थात्—

“(2) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी किसी तालाब, पोखर या अन्य जलाच्छादित भूमि को किसी व्यक्ति को असासी रूप में उठाने का अधिकार इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।”

धारा 198 का  
संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (4), (4-क) और (5) स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्—

“(4) कलेक्टर भूमि को किसी प्रदेशन से धुवध किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर ऐसे प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच करेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसी जांच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित तो वह प्रदेशन और पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है।

(5) किसी प्रदेशन या पट्टा को उपधारा (4) के अधीन निरस्त करने के लिये कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा, जब तक कि उस व्यक्ति पर, जिसके पक्ष में; प्रदेशन या पट्टा दिया गया था या उसके विधिक प्रतिनिधियों पर कारण बताने के लिए नोटिस तामील न कर दी जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी प्रदेशन या पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाहियों में ऐसी नोटिस आवश्यक न होगी जहां ऐसी कार्यवाहियाँ 18 अगस्त, 1980 को कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन रही हों।

(6) उपधारा (5) में उल्लिखित कारण बताने के लिये प्रत्येक नोटिस—

(क) 10 नवम्बर, 1980 (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) के पूर्व किये गये भूमि प्रदेशन की स्थिति में उक्त दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व, और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये भूमि प्रदेशन की स्थिति में, ऐसे प्रदेशन या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व,

जारी की जा सकती है।

(7) जहां किसी भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के अधीन निरस्त कर दिया जाय, वहां उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(एक) ऐसी भूमि में प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार, हक और स्वत्व समाप्त हो जायेगा, और भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जायेगी;

(दो) कलेक्टर निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाये रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(8) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

(9) जहां किसी व्यक्ति को धारा 132 में विनिर्दिष्ट कोई भूमि उक्त दिनांक के पूर्व किसी समय सीरदार या असक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में उठाई गई हो, और उपधारा (3) में उल्लिखित अनुज्ञेय क्षेत्र के संबंध में परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से इस प्रकार उठाई गई हो, वहां इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों में या उस प्रदेशन या पट्टे में, जिसके अधीन ऐसे व्यक्ति को वह भूमि उठाई गई थी, दी गयी किसी बात के होते हुए भी, उक्त दिनांक से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्—

(क) प्रदेशनग्रहीता या पट्टेदार ऐसी भूमि का असासी समझा जायगा और यह समझा जायगा कि वह वर्षानुवर्ष उक्त भूमि धृत कर रहा है, और उपर्युक्त सीमा तक भूमि का प्रदेशन या पट्टा उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिये अनियमित नहीं समझा जायगा;

(ख) ऐसी भूमि का प्रवेशन या पट्टा निरस्त करने के लिये कलेक्टर या किसी अन्य न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष उक्त दिनांक को विचाराधीन कार्यवाहियों; यदि कोई हों, उपशमित हो जायेंगी।

10—मूल अधिनियम की धारा 198-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी,

धारा 198-क  
का संशोधन

अर्थात्—

"198-क "(1) जहां धारा 195 या 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय, और प्रदेशनग्रीता से भिन्न किसी व्यक्ति का इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि पर अध्यासन है, वहां असिस्टेंट कलेक्टर प्रदेशनग्रीता के आवेदन पत्र पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

(2) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन वेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसकी किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेशनग्रीता को दिया जाय।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का, मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि—

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है जिसके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही है, और

(ख) प्रदेशनग्रीता ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर वेदखल कर सकता है, और प्रदेशनग्रीता को ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।

(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश की पुष्टि न्यायालय द्वारा की जायेगी।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति के आवेदन पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन अपराध का संज्ञित विचारण किया जा सकता है।

(7) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अन्तिम अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा।

(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानतो होगा।

11—मूल अधिनियम की धारा 201 में, शब्द और अंक "धारा 206 या 212" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 212" रख दिये जायेंगे।

धारा 201 का  
संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 204 में,—

धारा 204  
संशोधन

(क) शब्द "सौरदार" के स्थान पर शब्द "असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर" रख दिये जायेंगे;

(ख) अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी व्यक्ति द्वारा घत किसी भूमि के सम्बन्ध में किसी असामी को कोई ऐसा अधिकार प्रोद्भूत न होगा।"

धारा 210 का  
संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 210 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित आदिम जाति के किसी भूमिधर या असादी द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में खण्ड (क) से (ग) में उल्लिखित परिणाम नहीं होंगे।”

नयी धारा 211  
का बढ़ाया जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 210 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

“211 (1)—जहां अनुसूचित आदिम जाति के किसी खातेदार द्वारा धृत कोई भूमि ऐसे खातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो, वहां असिस्टेंट कलक्टर, इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे खातेदार के आवेदन-पत्र पर, या स्वप्रेरणा से अध्यासी को बेदखल करने के पश्चात्, उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये उसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक समझे जाय।

(2) अहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो तीन माह से कम नहीं होगी, और जुर्माना से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है किन्तु जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने वाला कोई न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को ऐसी भूमि या उसके किसी भाग से सरसरी तौर पर बेदखल करने के पश्चात् ऐसी भूमि का कब्जा खातेदार को दिलाया जाय और ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य कार्यवाही पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सके, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बेदखल किया जा सकेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अज्ञमानती होगा, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

(5) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा।”

धारा 229-अ  
का संशोधन

14-क—मूल अधिनियम की धारा 229-अ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्या-कृत कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्याकृत उपधारा के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्—

“(2) उपधारा (1) की कोई बात धारा 122-ख की उपधारा 4-अ के अधीन दायर किये गये वाद पर लागू नहीं होगी।”

धारा 287-क  
का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 287-क में, शब्द “किसी बकाया मालगुजारी” के स्थान पर शब्द “मालगुजारी की किसी बकाया” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 330 का  
संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 330 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा और सदैव से रखा गया समझा जायेगा, अर्थात्—

“(ग) अध्याय दस के अधीन मालगुजारी का निर्धारण या उसकी वसूली या मालगुजारी की बकाया की तरह वसूली योग्य किसी धनराशि की वसूली।”

## अध्याय तीन

### यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

17—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 33 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

यू० पी० ऐक्ट  
संख्या 3 सन्  
1901 की धारा  
33 का संशोधन

“(4) उपधारा (1) के अधीन जब-जब वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाय, कलक्टर उसकी तैयारी के उपरांत यथाशक्य शीघ्र, प्रत्येक उस व्यक्ति के निमित्त जो भूमिधर (चाहे संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार अभिलिखित हो, एक जोत वही (पास-बुक) नियत रीति से और नियत शुल्क का (जो मालगुजारी की वकाया की भाँति वसूल किया जा सकेगा) भुगतान करने पर, तैयार करायेगा और उसे दिलवायेगा जिसमें उसकी उन सभी जोतों के विषय में, जिनके संबंध में वह (चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) उस प्रकार अभिलिखित है, वार्षिक रजिस्टर के ऐसे उद्धरण होंगे जिन्हें नियत किया जाय:

प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त जोतों की स्थिति में, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह पर्याप्त होगा कि जोत वही (पास-बुक) अभिलिखित सह अंशधारियों में से केवल ऐसे एक या एकाधिक को जो नियत किये जायें, दी जाय।

स्पष्टीकरण—जोत वही (पास-बुक) किसी खातेदार की, भूमिधर (चाहे वह संक्रमणीय अधिकार वाला हो या नहीं), असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में उसके द्वारा धृत भूमि के संबंध में समस्त जोतों के लिये संहत पास-बुक होगी।”

18—मूल अधिनियम की धारा 183 में, शब्द “किसी वकाया मालगुजारी” के स्थान पर शब्द “मालगुजारी की किसी वकाया” रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 183 का  
संशोधन

## अध्याय चार

### जोनसार बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

19—जोनसार बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 26 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम  
संख्या 11 सन्  
1956 की धारा  
26 का संशोधन

“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे परगने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 245 निम्नलिखित परिष्कारों के साथ लागू होगी, अर्थात्,—

(एक) डेढ़ एकड़ भूमि की गणना एक एकड़ के रूप में की जायगी ;

(दो) किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के अध्याय दो के अधीन किये गये बन्दोबस्त पर स्वीकृत लगान की अधिकतम दरें एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न हों, उक्त धारा 245 की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड के खण्ड (i) में आये हुए शब्द “पांच रुपये” और “दस रुपये” के स्थान पर क्रमशः शब्द “तीन रुपये” और “पांच रुपये” रख दिये जायेंगे, और उसके खण्ड (ii) में, शब्द “दस रुपये” और “बीस रुपये” के स्थान पर क्रमशः शब्द “छः रुपये” और “दस रुपये” रख दिये जायेंगे।”

## अध्याय पांच

### उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 48 में—

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
5 सन् 1954  
की धारा 48  
का संशोधन

(1) उपधारा (1) में शब्द, “प्राधिकारी द्वारा दी गयी” के पश्चात् शब्द “अन्तर्वर्ती प्राज्ञा से भिन्न” रख दिये जायेंगे,

(2) वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्—

“स्पष्टीकरण—(2) इस धारा के प्रयोजनार्थ पद “अन्तर्वर्ती आज्ञा” का तात्पर्य किसी मामले या कार्यवाही के संबंध में ऐसे आदेश से है जो उस मामले या कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले या उसके संपार्श्विक किसी विषय को निर्णीत करते हुए भी उस मामले या कार्यवाही का अन्तिम रूप से निस्तारण करने का प्रभाव नहीं रखता है।”

धारा 49 का  
संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 49 में, निम्नलिखित प्रांतवन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्—

“किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा की कोई बात किसी ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार किसी गांव सभा को कब्जा दिया गया हो, या दिया गया समझा जाय, उत्तर प्रदेश जमींदारी—विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ख के अधीन कार्यवाहियां प्रारम्भ करने से असिस्टेंट कलेक्टर को प्रवारित नहीं करेगी।”

### अध्याय छः

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 1  
सन् 1961 की  
धारा 27 का  
संशोधन

22—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 में,—

(एक) उपधारा (6) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

“(क) 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये किसी बन्दोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, उक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये किसी बन्दोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व”;

(दो) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :—

“(6-क) जहाँ किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया हो, और जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया हो उससे भिन्न किसी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में अध्यासन हो, वहाँ कलेक्टर उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था, आवेदन पर उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्प्रेरण से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

(6-ख) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहाँ वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो तीन मास से कम नहीं होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझे, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाय जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था।



(6-ग) जहां उपधारा (6-ख) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ-पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि—

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है जिसके संबंध में ऐसी कार्यवाही है; और

(ख) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है।

वहां न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, और उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है।

(6-घ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वहां उपधारा (6-ग) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा।

(6-ङ) जहां किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय।

(6-च) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (6-ख) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानती होगा और उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

(6-छ) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी के अतिरिक्त अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा।”

### अध्याय सात

### उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1976 का संशोधन

23—उत्तर प्रदेश विधि (बिहार से अन्तरित राज्य क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

“(कक) “अनुसूचित ग्राम” का तात्पर्य अन्तरित राज्य क्षेत्रों में समाविष्ट और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्राम से है;”

24—मूल अधिनियम धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द “अनुसूची” के स्थान पर शब्द “प्रथम अनुसूची” रख दिये जायेंगे।

25—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

“3-क (1) जहां कोई व्यक्ति जिसका 15 अक्टूबर, 1976 को और इस धारा के कतिपय अध्यासियों को प्रारम्भ के दिनांक को भी किसी अनुसूचित ग्राम में स्थित किसी भूमि पर अध्यासन रहा है और वह भूमि ऐसी भूमि है जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की

धारा 132 के उपबन्ध,—

(क) लागू होते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से सम्बद्ध गांव समा की ओर से भूमि धारण करने वाला असामी हो जायेगा और हो गया समझा जायेगा ;

(ख) लागू नहीं होते हैं, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से, ऐसी भूमि के संबंध में सक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जायगा और हो गया समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश  
अधिनियम संख्या  
52 सन् 1976  
की धारा 2  
का संशोधन

धारा 3 का  
संशोधन

नई धारा 3-क  
का बढ़ाया जाना

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।"

द्वितीय अनुसूची  
का बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की वर्तमान अनुसूची को पुनः संख्यांकित करके उसकी प्रथम अनुसूची कर दी जायगी, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रथम अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"द्वितीय अनुसूची

(धारा 3—क देखिए)

अनुसूचित ग्रामों के नाम

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1—मिखनपुरा या भिखारीपुरा         | 16—नौबरार 1873 मूतल्लिका बेलसीपाह |
| 2—शाहपुर दिघवारा                 | 17—नौबरार (1) मूतल्लिका सरवनेपुर  |
| 3—आराजी माफी अजोरपुर             | 18—नौबरार (1) मूतल्लिका पलिया     |
| 4—शिवपुर गंगवरार                 | 19—सोभापुर                        |
| 5—बिजौरा गंगवरार                 | 20—पड़री                          |
| 6—सीतलपट्टी गंगवरार              | 21—पंकौली                         |
| 7—चतुरभुजतरी गंगवरार             | 22—असमानपुर                       |
| 8—गोविन्दपुर गंगवरार             | 23—गोविन्दपुर                     |
| 9—डांगराबाद                      | 24—चतुरभुजपुर                     |
| 10—बुलापुर                       | 25—अलखदियरा                       |
| 11—हरदेव छपरा                    | 26—पोखरा                          |
| 12—हरसेवक छपरा                   | 27—टोला बड़े बाबू                 |
| 13—चीवे छपरा                     | 28—तुलापुर (2) पोरसन              |
| 14—कवलापति छपरा उर्फ दुबे छपरा   | 29—दुर्जनपुर                      |
| 15—नौबरार (1) मूतल्लिका बेलसीपाह | 30—उधोपुर"                        |

अध्याय आठ

प्रकीर्ण

संक्रमणकालीन  
उपबन्ध

27—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 122—ख, जैसी कि वह इस धारा के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को किसी अधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थीं, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित की जायेंगी मानों यह अधिनियम पारित न किया गया हो;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 198, जैसी कि वह 18 अगस्त, 1980 को थी, के अधीन किसी भूमि के प्रदेशन या पट्टा के निरसन की सभी कार्यवाहियां जो इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक को किसी अधिकारी, न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन थीं, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निस्तारित की जायेंगी।

28—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्वारा निरसन और अपवाद  
निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित अध्याय दो, तीन, चार, पांच, छः और सात में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तदनु रूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

गंगा वरुण सिंह,  
सचिव।

No. 1548(2)/XVII-V—1-104-1980

Dated Lucknow, August 20, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1982), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on May 11, 1982.

# THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1982

(U. P. ACT NO. 20 OF 1982)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, U. P. Land Revenue Act, 1901, the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953, the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 and the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty Second Year of the Republic of India as follows:

## CHAPTER I

### Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1982.

Short title and  
commencement.

(2) Section 9 shall be deemed to have come into force on August 18, 1980, section 19 shall be deemed to have come into force on July 1, 1976, sections 2 to 7 and 12 to 14 and 27 shall be deemed to have come into force on June 3, 1981 and sections 8, 10, 11, 15 to 18 and 20 to 26 shall be deemed to have come into force on November 10, 1980 and the remaining provisions shall come into force at once.

## CHAPTER II

## Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950

Amendment of  
section 122-B  
of U. P. Act I  
of 1951.

2. In section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for sub-sections (1) to (4-E), the following sub-sections shall be substituted, namely:

“(1) Where any property vested under the provisions of this Act in a Gaon Sabha or a local authority is damaged or misappropriated or where any Gaon Sabha or local authority is entitled to take or retain possession of any land under the provisions of this Act and such land is occupied otherwise than in accordance with the provisions of this Act, the Land Management Committee or Local Authority, as the case may be, shall inform the Assistant Collector concerned in the manner prescribed.

(2) Where from the information received under sub-section (1) or otherwise, the Assistant Collector is satisfied that any property referred to in sub-section (1) has been damaged or misappropriated or any person is in occupation of any land, referred to in that sub-section, in contravention of the provisions of this Act, he shall issue notice to the person concerned to show cause why compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation as mentioned in such notice be not recovered from him or, as the case may be, why he should not be evicted from such land.

(3) If the person to whom a notice has been issued under sub-section (2) fails to show cause within the time specified in the notice or within such extended time not exceeding three months from the date of service of such notice on such person, as the Assistant Collector may allow in this behalf, or if the cause shown is found to be insufficient, the Assistant Collector may direct that such person may be evicted from the land and may for that purpose, use, or cause to be used such force as may be necessary and may direct that the amount of compensation for damage, misappropriation or wrongful occupation be recovered from such person as arrears of land revenue.

(4) If the Assistant Collector is of opinion that the person showing cause is not guilty of causing the damage or misappropriation or wrongful occupation referred to in the notice under sub-section (2) he shall discharge the notice.

✓(4-A) Any person aggrieved by the order of the Assistant Collector under sub-section (3) or sub-section (4) may, within thirty days from the date of such order prefer, a revision before the Collector on the grounds mentioned in clauses (a) to (e) of section 333.

(4-B) The procedure to be followed in any action taken under this section shall be such as may be prescribed.

(4-C) Notwithstanding anything contained in section 333 or section 333-A, but subject to the provisions of this section—

(i) every order of the Assistant Collector under this section shall, subject to the provisions of sub-sections (4-A) and (4-D), be final.

(ii) every order of the Collector under this section shall, subject to the provisions of sub-section (4-D), be final.

✓(4-D) Any person aggrieved by the order of the Assistant Collector or Collector in respect of any property under this section may file a suit in a court of competent jurisdiction to establish the right claimed by him in such property.

✓(4-E) No such suit as is referred to in sub-section (4-D) shall lie against an order of the Assistant Collector if a revision is preferred to the Collector under sub-section (4-A).

*Explanation*—For the purposes of this section, the expression ‘Collector’ means the officer appointed as Collector under the provisions of the U.P. Land Revenue Act, 1901 and includes an Additional Collector.”

3. For section 157-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of section 157-A.

"157-A. (1) Without prejudice to the restrictions contained in sections 153 to 157, no *bhumidhar* or *asami* belonging to a Scheduled Caste shall have the right to transfer any land by way of sale, gift, mortgage or lease to a person not belonging to a Scheduled Caste, except with the previous approval of the Collector:

Provided that no such approval shall be given by the Collector in case where the land held in Uttar Pradesh by the transferor on the date of application under this section is less than 1.26 hectares or where the area of land so held in Uttar Pradesh by the transferor on the said date is after such transfer, likely to be reduced to less than 1.26 hectares.

(2) The Collector shall, on an application made in that behalf in the prescribed manner, make such inquiry as may be prescribed."

4. After section 157-A of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:

Insertions section 7 and 157-C.

"157-B. (1) Without prejudice to the restrictions contained in sections 153 to 157, no *bhumidhar* or *asami* belonging to a Scheduled Tribe shall have the right to transfer by way of sale, gift, mortgage or lease or otherwise any land to a person not belonging to a Scheduled Tribe.

157-C. Notwithstanding anything contained in sections 157-A and 157-B, a *bhumidhar* or *asami* belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe may mortgage without possession his holding or part thereof in the circumstances specified in sub-section (3) of section 152.

*Explanation*—In this Chapter, the expressions 'Scheduled Castes' and 'Scheduled Tribes' shall mean respectively the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes specified in relation to Uttar Pradesh under Articles 341 and 342 of the Constitution."

5. Section 163 of the principal Act, shall be omitted.

Omission of section 163.

6. For sections 166 and 167 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

Substitution of sections 166 and 167.

"166. Every transfer made in contravention of the provisions of this Act shall be void.

167. (1) The following consequences shall ensue in respect of every transfer which is void by virtue of section 166, namely—

(a) the subject-matter of transfer shall, with effect from the date of transfer, be deemed to have vested in the State Government free from all encumbrances;

(b) the trees, crops and wells existing on the land on the date of transfer shall, with effect from the said date, be deemed to have vested in the State Government free from all encumbrances;

(c) the transferee may remove other movable property or the materials of any immovable property existing on such land on the date of transfer within such time as may be prescribed.

(2) Where any land or other property has vested in the State Government under sub-section (1), it shall be lawful for the Collector to take over possession over such land or other property and to direct that any person occupying such land or property be evicted therefrom. For the purposes of taking over such possession or evicting such unauthorised occupants, the Collector may use or cause to be used such force as may be necessary."

Amendment of  
section 169.

7. In section 169 of the principal Act, in sub-section (2-A), for the words, figures and letters "section 157-A", the words, figures and letters "sections 157-A and 157-B" shall be *substituted*.

Amendment of  
section 197.

8. Section 197 of the principal Act, shall be *renumbered* as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:

"(2) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, the right to admit any person as *asami* of any tank, pond or other land, covered by water shall be regulated by the rules made under this Act."

Amendment of  
section 198.

9. In section 198 of the principal Act, for sub-sections (4), (4-A) and (5), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:

"(4) The Collector may of his own motion and shall on the application of any person aggrieved by an allotment of land inquire in the manner prescribed into such allotment and if he is satisfied that the allotment is irregular, he may cancel the allotment and the lease, if any.

(5) No order for cancellation of an allotment or lease shall be made under sub-section (4), unless a notice to show cause is served on the person in whose favour the allotment or lease was made or on his legal representatives :

Provided that no such notice shall be necessary in proceedings for the cancellation of any allotment or lease where such proceedings were pending before the Collector or any other court or authority on August 18, 1980.

(6) Every notice to show cause mentioned in sub-section (5) may be issued—

(a) in the case of an allotment of land made before November 10, 1980 (hereinafter referred to as the said date), before the expiry of a period of two years from the said date; and

(b) in the case of an allotment of land made on or after the said date, before the expiry of a period of five-years from the date of such allotment or lease.

(7) Where the allotment or lease of any land is cancelled under sub-section (4), the following consequences shall ensue, namely—

(i) the right, title and interest of the allottee or lessee or any other person claiming through him in such land shall cease and the land shall revert to the Gaon Sabha;

(ii) the Collector may direct delivery of possession of such land forthwith to the Gaon Sabha after ejectment of every person holding or retaining possession thereof and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(8) Every order made by the Collector under sub-section (4) shall, subject to the provisions of section 333, be final.

(9) Where any person has been admitted to any land specified in section 132 as a *sirdar* or *bhumidhar* with non-transferable rights at any time before the said date and such admission was made with the previous approval of the Assistant Collector in-charge of the Sub-Division in respect of the permissible area mentioned in sub-section (3), then notwithstanding anything contained in other provisions of this Act or in the terms and conditions of the allotment or lease under which such person was admitted to that land, the following consequences shall, with effect from the said date ensue, namely—

(a) the allottee or lessee shall be deemed to be an *asami* of such land and shall be deemed to be holding the same from year to year, and the allotment or lease of the land to the extent mentioned above shall not be deemed to be irregular for the purposes of sub-section (4);

(b) the proceedings, if any, pending on the said date before the Collector or any other court or authority for the cancellation of the allotment or lease of such land, shall abate."

10. For section 198-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:

Substitution of section 198-A.

"198-A. (1) Where any land referred to in section 195 or section 197 is allotted to any person whether as a <sup>Restoration of possession to Gaon Sabha allottees.</sup> *Bhumidhar* with non-transferable rights or as an *Asami*, and any person other than the allottee is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act, the Assistant Collector may of his own motion and shall on the application of the allottee, put him in possession of such land and may, for that purpose use or cause to be used such force as he considers necessary.

(2) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees :

Provided that the court convicting the accused may while passing the sentence direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper be paid to the allottee as damages for use and occupation.

(3) Where in any proceeding under sub-section (2), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken, is satisfied by affidavit or otherwise—

(a) that the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of the Act, and

(b) that the allottee is entitled to the possession of such land the court may summarily evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the allottee in possession of such land.

(4) Where in any proceeding under sub-section (2) the accused is convicted, the interim order passed under sub-section (3) shall be confirmed by the court.

(5) Where in any proceeding under sub-section (2) the accused is acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land the court shall, on the application of such person, direct that delivery or possession be made to him.

(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, an offence under sub-section (2) may be tried summarily.

(7) For the purpose of speedy trial of offence under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification, constitute special courts consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of a Judicial Magistrate of the First Class.

(8) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable."

11. In section 201 of the principal Act, for the words and figures "section 206 or 212", the word and figure "section 212" shall be substituted.

Amendment of section 201.

12. In section 204 of the principal Act,—

(a) for the word "*sirdar*", the words "*bhumidhar* with non-transferable rights," shall be substituted;

Amendment of section 204.

(b) the following proviso shall be inserted at the end, namely:

"Provided that no such rights shall accrue to an *asami* in respect of any land held by a person belonging to a Scheduled Tribe."

Amendment of  
section 210.

13. In section 210 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :

"Provided that the consequences mentioned in clauses (a) to (c) shall not ensue in respect of any land held by a *bhumidhar* or *asami* belonging to a Scheduled Tribe."

Insertion  
section 211.

14. After section 210 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"211. (1) Where any land held by a tenure-holder belonging to a Scheduled Tribe is in occupation of any person other than such tenure-holder, the Assistant Collector may *suo motu* or on the application of such tenure-holder, put him in possession of such land after evicting the occupant and may, for that purpose use or cause to be used such force as may be considered necessary, anything to the contrary contained in this Act notwithstanding.

(2) Where any person, after being evicted from any land under sub-section (1), re-occupies the land or any part thereof without any lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with a fine which may extend to three thousand rupees but which shall not be less than one thousand rupees.

(3) Any court convicting a person under sub-section (2) may make an order to put the tenure-holder in possession of such land after evicting the person summarily from such land or any part thereof and such person shall be liable to eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under any other law for the time being in force.

(4) Every offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable and non-bailable and notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, may be tried summarily.

(5) For the purpose of speedy trial of offence, under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification constitute special courts consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of Judicial Magistrate of the first class.

Amendment of  
section 229-D.

14-A. Section 229-D of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to a suit filed under sub-section (4-D) of section 122-B."

Amendment of  
section 287-A.

15. In section 287-A of the principal Act, for the words "arrear of revenue" wherever occurring the words "arrears of land revenue" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of  
section 330.

16. In section 330 of the principal Act, for clause (c), the following clause shall be substituted and be deemed always to have been substituted namely—

"(c) the assessment or collection of land revenue under Chapter X or the recovery of any sum of money recoverable as arrears of land revenue."

### CHAPTER III

#### Amendment of the U. P. Land Revenue Act, 1901

Amendment of  
section 33 of  
U. P. Act no. III  
of 1901.

17. In section 33 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely :

"(4) Every time when annual register is prepared under sub-section (1) the Collector shall, as soon as may be after its preparation, cause to be prepared and supplied to every person 'recorded as *bhumidhar*' whether with or without transferable rights, *assami* or



Government Lessee a Jot Bahi (Pass Book) which shall contain such extract from the annual register relating to all holdings of which he is so recorded (either solely or jointly with others) and in such manner and on payment of such fee, which shall be realisable as arrears of land revenue, as may be prescribed:

Provided that in the case of joint holdings it shall be sufficient for the purposes of this sub-section if the Jot Bahi (Pass Book) is supplied only to such one or more of the recorded co-sharers as may be prescribed.

*Explanation*—The Jot Bahi (Pass Book) shall be consolidated pass-book for all the holdings of a tenure-holder in respect of land held by him as *bhumidhar* whether with or without transferable rights, *asami* or Government Lessee."

18. In section 183 of the principal Act, for the words "arrears of revenue" wherever occurring the words "arrears of land revenue" shall be substituted and be deemed always to have been substituted.

Amendment of section 183.

#### CHAPTER IV

##### *Amendment of the Jaunsar Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956*

19. In section 36 of the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:

Amendment of section 36 of U. P. Act no. XI of 1956.

"Provided that section 245 of the said Act shall, in relation to such Pargana, apply with the following modification, namely—

(i) one and a half acres of land shall count as one acre ;

(ii) in relation to any local area in which the maximum rent rates sanctioned at the settlement carried out under Chapter II of this Act, do not exceed rupee one per acre, the words 'rupees five' and 'rupees ten' in clause (i) of the proviso to sub-section (2) of the said section 245 shall be substituted by the words 'rupees three' and 'rupees five' respectively, and the words 'rupees ten' and 'rupees twenty' in clause (ii) thereof shall be substituted by the words 'rupees six' and 'rupees ten' respectively."

#### CHAPTER V

##### *Amendment of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953*

20. In section 48 of the Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953 hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, —

Amendment of section 48 of U.P. Act no. V of 1954.

(i) in sub-section (1), after the words "propriety of any order" the words "other than an interlocutory order" shall be inserted;

(ii) the existing Explanation shall be re-numbered as Explanation (1) and after the Explanation as so re-numbered the following Explanation shall be inserted, namely:—

"*Explanation (2)*— For the purposes of this section the expression 'interlocutory order' in relation to a case or proceeding, means such order deciding any matter arising in such case or proceeding or collateral thereto as does not have the effect of finally disposing of such case or proceeding."

21. In section 49 of the principal Act, the following proviso shall be inserted, namely :—

Amendment of section 49.

"Provided that nothing in this section shall preclude the Assistant Collector from initiating proceedings under section 122-B of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 in respect of any land possession over which has been delivered or deemed to be delivered to a Gaon Sabha under or in accordance with the provisions of this Act."

## CHAPTER VI

*Amendment of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960*

Amendment of  
section 27 of  
U.P. Act no.  
1 of 1961.

22. In section 27 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960—

(i) in sub-section (6), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) in the case of any settlement made or lease granted before November 10, 1980, before the expiry of a period of two years from the said date, and;

(b) in the case of any settlement made or lease granted on or after the said date, before the expiry of a period of five years from the date of such settlement or lease.”;

(ii) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(6-A) Where any surplus land has been settled by the Collector under sub-section (3), and any person other than the person in whose favour such settlement was made is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act, the Collector may, of his own motion and shall on the application of the person in whose favour such settlement was made, put him in possession of such land and may for that purpose use or cause to be used such force as he considers necessary.

(6-B) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees:

Provided that the court convicting the accused may while passing the sentence direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper, be paid to the person in whose favour such settlement was made as damages for use and occupation.

(6-C) Where in any proceeding under sub-section (6-B), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken is satisfied by affidavit or otherwise—

(a) that the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of the Act; and

(b) that the person in whose favour such settlement was made is entitled to the possession of such land;

the court may summarily evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the person in whose favour such settlement was made in possession of such land.

(6-D) Where in any such proceeding, the accused is convicted the interim order passed under sub-section (6-C) shall be confirmed by the court.

(6-E) Where in any such proceeding, the accused is acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land, the court shall, on the application of such person, direct that delivery of possession be made to him.

(6-F) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (6-B) shall be cognizable and non-bailable and may be tried summarily.

(6-G) For the purpose of speedy trial of offences under this section, the State Government may, in consultation with the High Court, by notification, constitute, special courts consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of a Judicial Magistrate of the first class.”

CHAPTER VII

*Amendment of the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976*

23. In section 2 of the Uttar Pradesh Laws (Extension to Territories Transferred from Bihar) Act, 1976, hereinafter in this Chapter referred to as principal Act, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

Amendment of section 2 of U.P. Act 52 of 1976.

“(aa) ‘Scheduled Village’ means a village comprised in the transferred territories and specified in the Second Schedule.”

24. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1) for the words “The Schedule” the words “the first Schedule” shall be substituted.

Amendment of section 3.

25. After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of section 3-A.

“3-A. (1) *Conferment of tenurial rights on certain occupants*—Where any person is in occupation of any land, situate in a Scheduled village, on October 15, 1976 as well as on the date of commencement of this section, and such land is a land to which the provisions of section 132 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950—

(a) apply such person shall, with effect from the date of such commencement become and be deemed to have become an *asami* holding land on behalf of the Gaon Sabha concerned ;

(b) do not apply, such person shall, with effect from the date of such commencement become and be deemed to have become *bhumidhar* with transferable rights in respect of such land.

(2) The provisions of this section shall have effect, anything to the contrary contained in any law for the time being in force notwithstanding.”

26. The existing Schedule to the principal Act, shall be re-numbered as the First Schedule, and after the First Schedule as so re-numbered, the following Schedule shall be inserted, namely:—

Insertion of the Second Schedule.

“THE SECOND SCHEDULE

(See SECTION 3-A)

*Names of the Scheduled villages*

- |   |  |
|---|--|
| 1. Bhikhanpura or Bhikharipura                | 16. Naubarar of 1873 appg. to Belsipah |
| 2. Shahpur Dighwara                           | 17. Naubarar I appg. to Sarwanpur      |
| 3. Arazi Mafi Anjorpur                        | 18. Naubarar I appg. to Palia          |
| 4. Sheopur Gangabarar                         | 19. Sobhapur                           |
| 5. Bijaura Gangabarar                         | 20. Pandari                            |
| 6. Sital Patti Gangabarar                     | 21. Paikauli                           |
| 7. Chaturbhujtari Gangabarar                  | 22. Asmanpur                           |
| 8. Govindpur Gangabarar                       | 23. Govindpur                          |
| 9. Dangrabad                                  | 24. Chaturbhujpur                      |
| 10. Bulapur                                   | 25. Alakh Diara                        |
| 11. Hardeo Chhapra                            | 26. Pokhara                            |
| 12. Harsewak Chhapra                          | 27. Tola Bare Babu                     |
| 13. Chaubechhapra                             | 28. Tulapur II Portion                 |
| 14. Kaulapat Chhapra <i>urf</i> Dubeychhapra. | 29. Durjanpur                          |
| 15. Naubarar I appg. to Belsipah              | 30. Udhopur.”                          |

## CHAPTER VIII

*Miscellaneous*

Transitory provision. <sup>13</sup>

27. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh Zamin-dari Abolition and Land Reforms Act, 1950—

(a) all proceedings under section 122-B of the said Act as it existed immediately before the commencement of this section and pending before any officer, court or authority on the date of such commencement shall be disposed of in accordance with the provisions of the said Act as if this Act had not been passed ;

(b) all proceedings for the cancellation of allotment or lease of land under section 198 of the said Act as it existed on August 18, 1980 and pending before an officer, court or authority on the date of commencement of this section shall be disposed of in accordance with the provisions of the said Act as amended by this Act.

Repeal and savings,

28. (1) The Uttar Pradesh Land Laws (Second Amendment) Ordinance, 1981 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the enactments referred to in Chapters II, III, IV, V, VI and VII as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of such enactments as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,

*Sachiv.*

U. P. Or-  
nance no  
of 1981.